









# एजुकेशन प्री-समित में हुए 28 हजार करोड़ के 507 एम.ओ.यू. : भजनलाल शर्मा

जयपुरा कभी मरूपीके रूप में पहचान रखने वाला हमारा राजस्थान निरंतर प्रगति, समृद्धि और उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास और जनता के हितोत्तरीय राइजिंग राजस्थान जैसा ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व आयोजन आयोजित होने जा रहा है। इससे पूर्व प्रदेश की शिक्षा में नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करने, सकारात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न उद्देश्यों को साकार करने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की दिशा में 6 नवंबर को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, टॉक रोड, जयपुर में एजुकेशन प्री-समित 2024 का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह सम्मेलन न केवल शिक्षा क्षेत्र के भामाशाह, दानदाता, और हितधारकों को एक साथ लाएगा, बल्कि शिक्षा के भविष्य के विकास हेतु रणनीतियों और नवाचारों पर विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे।



एजुकेशन प्री समिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे।

व खेल में विकास की नई राह खोलेंगे। राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और हालांकि हमारे पास तैयारी के लिए सीमित समय था, लेकिन हम आपके सहयोग से इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम होंगे। हम 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चाहे खनन हो, स्वास्थ्य हो या ऊर्जा, सभी क्षेत्रों में समझौता ज्ञानों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजस्थान के लिए आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा।" मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कुशल नेतृत्व में हो रही इस प्री-समित में 28 हजार करोड़ के 507 एमओयू किए गए हैं, जो शिक्षा, तकनीकी-उच्च शिक्षा, कौशल विकास

गुणवत्ता में सुधार, नए शैक्षिक दृष्टिकोण, कौशल विकास की सहायता से शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के प्रयास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर उच्च-स्तरीय मंथन करना है। यह समिट राज्य की राजकीय शिक्षा में सुधार और उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बाद शिक्षा में नवनिर्माण का नया युग प्रारंभ होना सुनिश्चित किया जाने की उम्मीद है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि इस एमओयू के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल, ई-लर्निंग, डिजिटल शिक्षा, शिक्षा की

■ उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा आयोजन

■ नए शैक्षिक दृष्टिकोण, डिजिटल लर्निंग और रोजगारोन्मुखी कौशल एजुकेशन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश पर होगा गहन मंथन

इन उद्देश्यों की परिपूर्णता हेतु इस वृहत आयोजन में शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट नीति विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां, भामाशाह, दानदाता और प्रदेश की शिक्षा को नई दिशा देने वाले विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भविष्य का राजस्थान विजन को साकार करने के तीव्र प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। एजुकेशन प्री-समित इसी स्वर्णीय यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इस पड़ाव में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित निवेशक एवं अधिकारी मौजूद रहे।

## सी.एम. को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुरा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। साबरमल चौधरी ने अग्रिम जमानत की शर्त की अवहेलना कर अदालत को अनुमति के बिना विदेश जाने का आरोप लगाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में यह साबित नहीं है कि मामले में प्रार्थी का कोई हित जुड़ा हो या वह एफआईआर दर्ज कराने वाला हो। वह न तो मामले में पीड़ित है और ना ही उसे किसी प्रकार का नुकसान या उसका हित प्रभावित हुआ है। ऐसे में

उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई साल पहले आरोप पत्र पेश कर दिया है। इस एफआईआर में भजनलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसे अदालत ने 10 सितंबर, 2013 को स्वीकार कर सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। अग्रिम जमानत आदेश में शर्त लगाई गई थी कि भजनलाल बिना अदालत की अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि भजनलाल शर्मा जमानत की शर्त की अवहेलना कर बिना

## दिव्यांग को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

जयपुरा राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 से जुड़े मामले में दिव्यांग याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश गिरिजेश व्यास को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्राप्त सेनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने कॉलेज शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए गत वर्ष आवेदन मांगे थे। जिसमें याचिकाकर्ता ने दिव्यांग वर्ग की एलडी कैटेगरी में आवेदन किया। याचिकाकर्ता के पास बहु दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, जिसमें वह शरीर की दो दिव्यांगता से पीड़ित है।

## ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट से पहले जयपुर परकोटे को निखारेगा हैरिटेज नगर निगम आयुक्त अरूण कुमार हसीजा ने निगम अधिकारियों के साथ किया शहर में निरीक्षण

जयपुर (कासं) राजधानी जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जयपुर परकोटे की साफ-सफाई और यहां रंग-रोगन करवाने का काम होगा। हैरिटेज निगम आयुक्त अरूण कुमार हसीजा ने बुधवार को समिट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद परकोटा क्षेत्र का दौरा कर हालात भी जांचे।

आयुक्त अरूण हसीजा ने अफसरों से कहा कि, राइजिंग राजस्थान समिट में देश-विदेश से आमंत्रित अतिथि जयपुर आएंगे। इन मेहमानों को जयपुर की सौंदर्यता दिखे और वे गुलाबीनगरी की सुंदर छवि लेकर अपने साथ लौटें, इसी मंशा के साथ सभी लोग काम करें।

इसके लिए शहर की सफाई व्यवस्था सुधारों विशेष तौर पर दिल्ली रोड, आमेर, जलमहल, हवामहल, जय निवास उद्यान, पॉइंट पार्क और ताल कटोरा जैसे पर्यटन स्थलों की सफाई व्यवस्था मजबूत की जाए।

आयुक्त अरूण हसीजा ने सड़क की वाल पेंटिंग, सफाई व्यवस्था, रोड डिवाइडर पर पीधों की छंटाई के कार्य को भी समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने हैरिटेज निगम मुख्यालय में राइजिंग राजस्थान को लेकर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए कहा, जो कि 24 घंटे काम करेगा। इसके अलावा निगम की इंजीनियरिंग विंग को भी सड़क, डिवाइडर और जाली से संबंधित

जयपुरा जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। साबरमल चौधरी ने अग्रिम जमानत की शर्त की अवहेलना कर अदालत को अनुमति के बिना विदेश जाने का आरोप लगाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में यह साबित नहीं है कि मामले में प्रार्थी का कोई हित जुड़ा हो या वह एफआईआर दर्ज कराने वाला हो। वह न तो मामले में पीड़ित है और ना ही उसे किसी प्रकार का नुकसान या उसका हित प्रभावित हुआ है। ऐसे में

# देवली-उनियारा, झुंझुनूं और खींवर में त्रिकोणीय संघर्ष बिगड़ रहे पार्टियों के समीकरण

जयपुरा राजस्थान में हो रहे उपचुनाव में देवली और दोसा के अलावा झुंझुनूं और खींवर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सबसे ज्यादा रोमांच पैदा हुआ है। दरअसल इन सीटों पर बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा तो दाव पर लगी ही है। साथ ही इन सीटों के त्रिकोणीय मुकाबले ने भी चुनाव को काफी रोचक बना दिया है और यही कारण है कि रामगढ़, सलुंबर और चौरासी की जितनी चर्चा नहीं हो रही, उतनी इन चार सीटों की चर्चा हो रही है। सलुंबर में भाजपा और रामगढ़ में कांग्रेस सहानुभूति के आधार पर अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं चौरासी में बाप अपनी परंपरागत सीट को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। वैसे उपचुनाव के परिणाम कुछ भी हो लेकिन यह तय है कि कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव घाटे का सौदा साबित होंगे।

जहां तक सबसे रोमांचक मुकाबले की बात करें, तो वह देवली उनियारा में नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने वाले नरेश मीणा ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। वहीं भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर को भी कड़ा प्रयास करना पड़ रहा है। दरअसल नरेश मीणा के साथ में युवाओं की भारी भीड़ जुटने की वजह से दोनों पार्टियां परेशानी में हैं और नरेश मीणा ने बिना किसी बड़े नेता के साथ हुए बिना भी

■ नरेश मीणा और राजेंद्र गुर्जा ने कांग्रेस का संकट बढ़ाया, खींवर में हनुमान बेनीवाल की कड़ी परीक्षा

■ दोसा में पायलट, मुरारी और किरौड़ी की प्रतिष्ठा का चुनाव, सलुंबर में भाजपा तो रामगढ़ में कांग्रेस सहानुभूति के सहारे

दाव पर लगी है। जहां तक दोसा की बात करें, तो यहां डॉ किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन भाजपा के उम्मीदवार हैं। ऐसे में यहां पूरा चुनाव डॉ किरोड़ी लाल मीणा के कंधे पर है। दूसरी ओर कांग्रेस में उम्मीदवार डीसी बैरवा के चलते सचिन पायलट और सांसद मुरारी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। यहां जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं और कुछ वोटों का इधर से उधर होना परिणाम को बदल सकता है। ऐसे में यहां का चुनाव भी काफी रोमांचक भरा नजर आ रहा है। झुंझुनूं में कांग्रेस में फिर ओला परिवार से उम्मीदवार आने से एक चर्चा चल पड़ी है कि क्या कांग्रेस ओला परिवार के बाहर भी निकलेगी। इस बात का कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। वहीं भाजपा ने एक बार फिर राजेंद्र भांधू पर विश्वास जताया है। साथ ही इस बार भाजपा में झुंझुनूं में बगावत नहीं है। बबलू चौधरी का नामांकन वापस करवाकर भाजपा ने खुद को मुकाबले में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के लिए पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जा ने परेशानी खड़ी कर दी है। मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटों में राजेंद्र गुर्जा की चुनपैट कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होती लग रही है। यदि राजेंद्र गुर्जा के साथ आ रही भीड़ वोटों में तब्दील हो पाई, तो कांग्रेस को झुंझुनूं में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

# माइंस विभाग का “राइजिंग राजस्थान” प्री-समित 8 नवंबर को होगा

—कार्यालय संवाददाता—  
जयपुर। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त बताया कि 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित माइंस व पेट्रोलियम सेक्टर



प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने बुधवार को खान विभाग के प्री समिट के आयोजन स्थल का निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल, जेएस आशु चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जायजा लिया।

■ निवेश एम.ओ.यू. के साथ ही प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र के समग्र विकास पर होगा मंथन

■ राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक प्रदेश की खनिज संपदा थीम आधारित प्री-समित

■ खनन क्षेत्र के अब तक 70 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू संपन्न

■ समिट के दौरान प्रदर्शित होगी माइंस, पेट्रोलियम, सीजीडी गैस, रिफाइनरी से संबंधित ज्ञानवद्धर्क सामग्री

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में रोड शो व अन्य आयोजनों में अब तक 70 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को आयोजित प्री समिट में भी बड़ी संख्या में एमओयू हस्ताक्षरित होंगे।

टी. रविकान्त ने बताया कि माइनिंग सेक्टर के प्री समिट को अधिक उपयोगी व निवेशोन्मुखी बनाया जा रहा है। इस अवसर पर खनिज अन्वेषण, डाटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की भूमिका और मिन्नल एक्सप्लोरेशन में जियो इन्फोमेटिक्स की भूमिका पर धनबाद और कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर एसएस राय का विशेषज्ञ व्यक्तव्य और पर चर्चा होगी। इसी तरह से एक अन्य सत्र में डीप सीटेड बेस मेटल डिपोजिट्स लेड, जिंक, तांबा और संबंधित खनिजों पर अर्निन्ध बट्टाचार्य उप महानिदेशक जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विशेषज्ञ व्यक्तव्य देंगे और उस पर चर्चा होगी।

क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट और प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पर चर्चा का एक सत्र रखा गया है जिसमें सीएम्डी इंडियन रेयर अर्थ डॉ. दीपेंद्र सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर एमके पण्डित, शैलेन्द्र शर्मा क्षेत्रीय निदेशक एएमडी, जीएसआई से संजय सिंह, एनपीईए के निदेशक डॉ. येरी स्वामी पाटिल पेनसिल्ट होंगे तो इस सत्र को निदेशक जीएसआई हरीश मिश्रा मॉडरेट करेंगे। इसी तरह से खनिज संसाधन वृद्धि में खनन कंपनियों और निजी अन्वेषण संस्थाओं की भूमिका पर मंथन होगा। इस सत्र में सीएमडी एचसीएल घनश्याम शर्मा, एनपीईए के निदेशक डॉ. चेत्रामल्लिकार्जुन बी पाटिल, हिन्दुस्तान जिंक के निदेशक एक्सप्लोरेशन कुलदीप सिंह सोलंकी, माइनिंग टेक्निकल इजिट के प्रमुख मुस्तफा साबेर पेनसिल्ट होंगे और एस्के मिण्डा मॉडरेट होंगे।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि समिट में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को राजस्थान के खनिज व खनिज से जुड़ी जानकारीयें से रबर

## मेडिकल कॉलेज की याचिका खारिज

जयपुरा राजस्थान हाईकोर्ट ने आकस्मिक जांच में संसाधनों की कमियां पाए जाने पर मेडिकल कॉलेज की एच.बी.बी.एस. की सीटों कम करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश गिरिजेश व्यास को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता साइसेज सोसायटी, कोटा और सुधा मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए विचार दिए। अदालत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के डीन ने अपील के निर्णय के

■ एमबीबीएस की सीटें कम करने को दी थी चुनौती

दौरान सीटों पर प्रवेश के साथ कॉलेज की स्थापना को स्वीकार किया था। ऐसे में याचिकाकर्ता एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा हुआ है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया था। इस पर चिकित्सा

से नियमानुसार दुकान का नाम लिखने की समझाइश के लिए भी कहा। बैठक के तुरंत बाद आयुक्त ने क्षेत्र का दौरा भी किया। आयुक्त अरूण हसीजा ने चौड़ा रास्ता, जिपोलिया बाजार, अजमेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, सुधा चौक, आमेर रोड, रामगढ़ मोड और जल महल का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ जगहों पर गंदगी देख संबंधित अधिकारी को सख्त निर्देश देकर सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। जल महल की पाल पर टूटी टाइल को ठीक करने और सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता

श्रवन कुमार वर्मा, जोन उपायुक्त व अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे।

## सड़कों पर गंदगी देखकर नाराज हुई कुसुम यादव

जयपुरा जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, (जयपुर डेयरी) के द्वारा सरस उपभोक्ताओं तक शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में उपभोक्ताओं के घर तक सरस घी पहुंचाने की शुरुआत की गई। प्रथम सरस घी प्रो होम डिलीवरी स्कीम की शुरुआत अ.सी.डी.एफ. प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक श्रुति भाद्राज तथा जयपुर डेयरी के प्रबन्ध संचालक मनीष फौजदार ने डिलीवरी वाहन को हरी झण्डी दिखाकर की।

को सफाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। वहीं, नाइट स्विफिंग के तहत निगम द्वारा की का रही सफाई व्यवस्था में लगे सफाई कर्मियों की हाजिरी भी चेक की। महापौर कुसुम यादव ने बताया कि अगामी महीने में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान आयोजन में देश-विदेश से अतिथि जयपुर को निहारने आयेगा। ऐसे में वे शहर की अच्छी

याचिकाकर्ता ने कॉलेज स्थापना के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के समक्ष अनुमति के लिए आवेदन किया। इस पर पर राष्ट्रीय चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ने कुछ कमियां बताते हुए याचिकाकर्ता को गत तीन अप्रैल को नोटिस दिया। जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दे दिया। याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने आकस्मिक निरीक्षण कर संस्थान में संसाधनों के लिए फैकल्टी की कमी बताकर गव 4 जुलाई को 150 सीटों को घटाकर सीटों कर दी।





